



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-26042023-245440  
CG-JK-E-26042023-245440

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]  
No. 269]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग  
(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए)  
अधिसूचना

जम्मू, 6 अप्रैल 2023

सं. जेईआरसी-जेकेएल/रिग/2023/09: विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 91 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पिछले प्रकाशन के बाद, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:

## 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

- इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे:

## 2. परिभाषाएं

- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

a. "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

- b. "आयोग" का अर्थ जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है ;
- c. "समिति" का अर्थ प्रस्तावों के अनुरोध के मूल्यांकन के लिए आयोग द्वारा गठित समिति है;
- d. "सलाहकार" में कोई भी व्यक्ति शामिल है - जो आयोग, फर्म, निकाय या व्यक्तियों के संघ के रोजगार में नहीं है, जिसके पास या जिनके पास कोई विशेष ज्ञान, अनुभव या कौशल है या उसकी पहुंच है;
- e. "सचिव" का अर्थ आयोग के सचिव से है।
- 2.2 इन विनियमों में आने वाले ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

### 3. कार्यक्षेत्र

- 3.1 आयोग समय-समय पर विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिनके लिए आयोग के कर्मचारियों के भीतर कौशल उपलब्ध नहीं हैं या जहां नौकरी की प्रकृति विशिष्ट और समयबद्ध है या जहां आयोग सलाहकार की नियुक्ति को गुणवत्ता, लागत, समय या किसी अन्य विचार या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए कार्य को पूरा करने के लिए अनुकूल या अधिक प्रभावी और कुशल विधि मानता है और आम तौर पर आयोग को अपने कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए, यदि आयोग इसे आवश्यक समझता है तो परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है।
- 3.2 सलाहकारों की नियुक्ति के नियम और शर्तें प्रत्येक मामले में तैयार किए जाएंगे और काम देने से पहले सलाहकार और आयोग के बीच सहमति बनाई जाएगी।
- 3.3 अनुबंध की शर्तों में सलाहकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सटीक प्रकृति, प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय, और इस संबंध में अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के अनुसार प्रत्येक कार्य के संबंध में सलाहकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट आउटपुट का उल्लेख होगा।

### 4. नियुक्ति की अवधि

- 4.1 सलाहकार न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा:  
बशर्ते कि किसी विशिष्ट कार्य पर सलाहकार की प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी:  
बशर्ते आगे कि नियुक्ति की अवधि को इस शर्त के अधीन बढ़ाया जा सकता है कि सलाहकार की निरंतर नियुक्ति की अधिकतम अवधि किसी भी मामले में चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 5. सलाहकारों का वर्गीकरण

- 5.1 सलाहकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा: (क) संस्थागत सलाहकार, (ख) व्यक्तिगत सलाहकार, (ग) पेशेवर, विशेषज्ञ, और (घ) स्टाफ सलाहकार।

### 6. संस्थागत सलाहकार

आयोग, इस बात से संतुष्ट होने पर कि परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है, जो कि आयोग राय में, शायद एक फर्म, या एक कंपनी या एक संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से प्रदान की जाती है, एक संस्थागत सलाहकार को नियुक्त करेगा।

### 7. व्यक्तिगत सलाहकार

- 7.1 आयोग, एक व्यक्तिगत सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है जब वे इस बात से संतुष्ट होंगे कि परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है, जो कि आयोग राय में, किसी कार्य के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा अधिक कुशलता से निष्पादित की जा सकती है, जिसके लिए कर्मियों की टीमों की आवश्यकता नहीं है।

- 7.2 यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है या विभिन्न बाधाओं के कारण एक नियमित पद नहीं भरा जा सका है, तो आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए व्यक्तिगत सलाहकार भी नियुक्त किया जा सकता है।

- 7.3 व्यक्तिगत सलाहकार का मुख्यालय सामान्यतः आयोग का मुख्यालय होगा।

### 7.3 व्यक्तिगत सलाहकारों का वर्गीकरण

7.3.1 अनुभव के आधार पर, व्यक्तिगत सलाहकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा

वर्ग	नियुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव
सलाहकार	15 साल
वरिष्ठ कंसल्टेंट्स	10 वर्ष
कंसल्टेंट्स	3 वर्ष

7.3.2 आयोग कार्य की प्रकृति और परामर्श के विषय क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक पेशेवर योग्यता के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर सकता है।

7.3.3 आयोग उचित मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति की समग्र विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकता है।

### 8. पेशेवर विशेषज्ञ

विशेषज्ञ प्रकृति की व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता पर संतुष्ट होने पर आयोग अत्यावश्यक और विशिष्ट प्रकृति के मुद्दे पर सलाह के लिए एक पेशेवर विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।

### 9 स्टाफ कंसल्टेंट्स

यदि आयोग संतुष्ट है कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हो रही है या विभिन्न बाधाओं के कारण एक नियमित पद नहीं भरा जा सका है तो आयोग के कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए स्टाफ सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है।

### 10 संस्थागत सलाहकार की नियुक्ति

10.1 आयोग, इस बात से संतुष्ट होने पर कि किसी भी कार्य के लिए संस्थागत सलाहकार की सेवाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है, सचिव को निर्देश देगा कि वह विस्तृत संदर्भ की शर्तें तैयार करें या तैयार करवाएं।

10.2 सचिव किसी विशिष्ट कार्य के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए विस्तृत संदर्भ की शर्तें तैयार करेगा या तैयार करवाएगा और आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

10.3 कार्य के उद्देश्यों, लक्ष्यों और दायरे को निर्दिष्ट करने के लिए संदर्भ की शर्तें तैयार की जाएंगी और सलाहकार को अपने प्रस्ताव की तैयारी में मदद करने के लिए मौजूदा प्रासंगिक अध्ययनों की सूची और बुनियादी डेटा सहित पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि संदर्भ की शर्तें असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं और सर्वेक्षणों तथा संदर्भ की शर्तों में शामिल प्रत्येक कार्य से जुड़े अपेक्षित आउटपुट (उदाहरण के लिए रिपोर्ट, डेटा, सर्वेक्षण आदि) को भी सूचीबद्ध करेंगी।

बशर्ते कि जहां ज्ञान का हस्तांतरण और प्रशिक्षण एक उद्देश्य है, संदर्भ की शर्तें प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण देंगी।

10.4 आयोग द्वारा संदर्भ की शर्तों के अनुमोदन के बाद, सचिव को संस्थागत सलाहकार के रूप में नियुक्ति के हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावों का अनुरोध जारी करना चाहिए या जारी करवाना चाहिए और ऐसा प्रचार करना चाहिए जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जा सकता है।

10.5 आयोग या तो संयुक्त तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को आमंत्रित करने या तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को अलग-अलग आमंत्रित करने का निर्णय ले सकता है।

10.6 आयोग तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित कर सकता है।

### 11 प्रस्तावों के लिए अनुरोध

प्रस्तावों के अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-

11.1 परामर्शी सेवाओं के प्रावधान, योजना के विवरण, और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की तिथि, समय और पते के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आयोग के इरादे को बताते हुए आमंत्रण पत्र।

11.2 सलाहकारों को दी जाने वाली जानकारी में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए जो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करके और मूल्यांकन मानदंड और कारकों और उनके संबंधित भार और न्यूनतम पूर्व-योग्यता स्कोर और विशेष योग्यता खंड, यदि कोई हो, को इंगित करके उत्तरदायी प्रस्ताव तैयार करने में मदद करेगी।

11.3 उपरोक्त विनियम (10.3) के अनुसार इस संबंध में तैयार किए गए संदर्भ की शर्तें।

## 12 प्रस्तावों की प्राप्ति

12.1 आयोग वह समय निर्धारित करेगा जिसके भीतर परामर्शदाता अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

12.2 आयोग, जहां उचित समझे, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।

12.3 समय सीमा समाप्त होने के बाद तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावों में कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.4 प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

## 13 प्रस्तावों का मूल्यांकन

13.1 प्रस्ताव का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता और उद्धृत लागत दोनों के आधार पर किया जाएगा।

13.2 जहां आयोग निर्णय लेता है कि तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तब तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा होने तक समिति के पास वित्तीय प्रस्तावों तक पहुंच नहीं होगी।

13.3 इस संबंध में प्रस्ताव का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। समिति तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की बातचीत कर सकती है। जहां तकनीकी बातचीत आयोजित की जाती है, वही सलाहकारों की पूर्व-योग्यता से पहले आयोजित की जाएगी। वित्तीय प्रस्ताव के किसी भी पहलू के लिए वित्तीय बातचीत की जा सकती है, जिसमें कर्मचारियों के महीनों के लिए इकाई दर, आकस्मिक राशि, यात्रा और रहने के खर्च की एकमुश्त प्रतिपूर्ति और भुगतान की शर्तें शामिल हैं।

## 14 तकनीकी मूल्यांकन

14.1 तकनीकी मूल्यांकन उपरोक्त विनियम (13.3) के तहत नियुक्त समिति द्वारा नीचे विनियम (14.2) के तहत दिए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

14.2 प्रत्येक तकनीकी मानदंड को 1 से 100 के पैमाने पर अंकित किया जाएगा और फिर प्रत्येक मानदंड के अंकों को औसत तकनीकी स्कोर बनाने के लिए भारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए मूल्यांकन औसत तकनीकी स्कोर की गणना करने के लिए आयोग के अनुमोदन से समिति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में भार का उपयोग किया जाएगा:-

मापदंड	अंकन
असाइनमेंट के लिए सलाहकार का प्रासंगिक अनुभव	0.10 से 0.40
प्रस्तावित कार्यप्रणाली की गुणवत्ता	0.20 से 0.50
प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता	0.30 से 0.60
आयोग के कर्मचारियों को ज्ञान के हस्तांतरण की सीमा	0.05 से 0.35

टिप्पणी: आयोग द्वारा अनुमोदित अंकों का मिश्रण कुल 1 होगा।

विनियम (13.3) के तहत नियुक्त मूल्यांकन समिति बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रत्येक पैरामीटर को आवंटित किए जाने वाले भारांक (ऊपर निर्धारित सीमा में) का निर्णय करेगी और आवंटन के लिए आयोग के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी। आयोग के पास असाइनमेंट की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर अंकों के वितरण का अधिकार होगा।

14.3 जहां असाइनमेंट मुख्य कर्मचारियों के प्रदर्शन पर गंभीर रूप से निर्भर करता है, वहां प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करते हुए नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की योग्यता पर किया जाएगा:-

a) सामान्य योग्यताएं: सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, स्टाफ के रूप में सलाहकार फर्म में बिताया हुआ समय, विकासशील देशों में अनुभव, आदि।

b) असाइनमेंट के लिए पर्याप्तता: शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव, क्षेत्र, विषय और विशेष असाइनमेंट के लिए प्रासंगिकता।

- 14.4 तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, आयोग उन सलाहकारों को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता अंकों को पूरा नहीं करते थे या संदर्भ की शर्तों के प्रति अनुत्तरदायी माने जाते थे, और उनके वित्तीय प्रस्तावों को चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।
- 14.5 इसके साथ ही, जिन सलाहकारों ने तकनीकी मूल्यांकन के बाद न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा, अगर वे चाहें तो सलाहकारों को उद्घाटन के समय उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

### 15 वित्तीय मूल्यांकन

- 15.1 तकनीकी रूप से योग्य सलाहकारों के वित्तीय प्रस्ताव सलाहकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समिति द्वारा खोले जाएंगे जिनकी बोलियों को वित्तीय मूल्यांकन के लिए चुना गया है। प्रस्तावित कीमतों को जोर से पढ़ा जाएगा और कार्यवाही के मिनटों में दर्ज किया जाएगा।
- 15.2 सचिव किए जाने वाले वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा कराएंगे। अंकगणितीय त्रुटियां सुधारी जाएंगी। लागत भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएगी।
- 15.3 न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय स्कोर दिया जाएगा और अन्य प्रस्तावों को उनकी लागत के व्युत्क्रमानुपाती वित्तीय स्कोर दिया जाएगा।

### 16 वित्तीय और तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन

- 16.1 तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को भारित कर तथा उन्हें जोड़कर कुल अंक प्राप्त किये जायेंगे तथा उच्चतम कुल अंक वाले परामर्शदाता को आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुबंध करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा। तकनीकी और वित्तीय स्कोर के लिए मूल्यांकन प्रत्येक मामले में असाइनमेंट की जटिलता और गुणवत्ता के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, किसी भी मामले में वित्तीय स्कोर के लिए मूल्यांकन कभी भी 0.3 से अधिक नहीं होगा।
- 16.2 आयोग किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है यदि वे अप्रतिसादी या अनुपयुक्त पाए जाते हैं या तो वे संदर्भ की शर्तों के अनुपालन में प्रमुख कमियों को दर्शाते हैं या मूल अनुमान से काफी अधिक लागत शामिल करते हैं।

### 17 व्यक्तिगत सलाहकारों की नियुक्ति

व्यक्तिगत सलाहकारों को असाइनमेंट के लिए उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जा सकता है। आयोग सचिव को निर्देश दे सकता है कि वे आवश्यकता के अनुसार कार्य के दायरे और अन्य नियमों और शर्तों को इंगित करते हुए संदर्भ की शर्तें तैयार करें, जिन्हें अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। व्यक्तिगत सलाहकारों का चयन संदर्भों के आधार पर या उन लोगों में से किया जा सकता है जिन्होंने इस संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस के संदर्भ में आवेदन किया है। उनकी उपयुक्तता का निर्णय शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव, और, उपयुक्त के रूप में स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक प्रणाली और सरकारी संगठन के ज्ञान के आधार पर किया जाएगा।

- 17.1 न्यूनतम योग्यता और आयु मानदंड: इच्छुक उम्मीदवार के पास (ए) किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। (बी) उम्मीदवार को विद्युत अधिनियम, 2003, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, और लागू नीतियों, बिजली क्षेत्र से संबंधित कानूनी और नियामक ढांचे की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। (सी) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया और संबंधित मामलों के दौरान शामिल नियामक कार्यवाही के दौरान राज्यों / संयुक्त / केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगों को सहायता प्रदान करने में सिद्ध अनुभव होना चाहिए। (डी) आवेदन की तिथि पर 60 वर्ष की आयु तक का उम्मीदवार एक व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में काम करने के लिए पात्र है और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक आयोग को सेवाएं प्रदान कर सकता है; बाद में कोई आयु छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 18 व्यक्तिगत सलाहकारों के मामले में शुल्क और अन्य प्रभार

- 18.1 सिवाय जहां आयोग अन्यथा निर्देशित करता है, व्यक्तिगत सलाहकार को आम तौर पर असाइनमेंट की प्रकृति या मासिक शुल्क के आधार पर समेकित शुल्क के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- 18.2 व्यक्तिगत सलाहकारों के मामले में उप-विनियम (1) के अनुसार समेकित शुल्क के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि आयोग आकस्मिक प्रकृति के व्यय को शामिल करने के लिए सलाहकार को देय शुल्क के 10% से अधिक की अतिरिक्त राशि की अनुमति दे।

- 18.3 जहां सलाहकार को आयोग के मुख्यालय से दूर किसी स्थान पर आने-जाने और रहने पर खर्च करना पड़ता है, आयोग केंद्र सरकार के एक समूह ए अधिकारी को अनुमत श्रेणी से कम नहीं एक उपयुक्त श्रेणी द्वारा यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा और इन विनियमों के तहत देय शुल्क और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त, जितने दिनों के लिए आयोग उचित समझे, दैनिक भत्ते के भुगतान को प्राधिकृत करेगा।
- 18.4 इन विनियमों के अधीन व्यक्तिगत परामर्शदाताओं को देय शुल्क एवं अन्य प्रभार आयोग द्वारा परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त पूर्व एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को भी देय होंगे।
- 18.5 व्यक्तिगत सलाहकारों के लिए शुल्क

वर्ग	अधिकतम शुल्क प्रति व्यक्ति दिवस	दैनिक भत्ता
सलाहकार	रु.7500/-	बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए वास्तविक खर्च
वरिष्ठ कंसल्टेंट्स	रु.5500/-	बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए वास्तविक खर्च
कंसल्टेंट्स	रु.3000/-	बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए वास्तविक खर्च

#### टिप्पणी:

- आयोग के पास व्यक्तिगत सलाहकार के अनुभव और साख के आधार पर दैनिक/मासिक आधार पर व्यक्तिगत सलाहकार को देय शुल्क के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जाता है।
  - आयोग दैनिक भत्ते के रूप में अनुमेय राशियों को निर्दिष्ट करने, वह उचित सीमा निर्धारित करने जिसके भीतर वास्तविक व्यय को मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जानी है, और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दावे की तर्कसंगतता का आकलन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- 19 पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति आयोग द्वारा पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लेने पर, आयोग के सचिव प्रस्तावों को औपचारिक रूप देंगे। वह विशेष क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले, परामर्श कार्य को स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले और उनमें से प्रत्येक द्वारा मांगे गए शुल्क के आधार पर कम से कम दो पेशेवरों की एक सूची तैयार करेगा।
- आयोग इस तरह के शुल्क के भुगतान पर और ऐसी शर्तों पर सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ के नाम को मंजूरी दे सकता है, जैसा उचित समझा जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित शुल्क कार्य के एक व्यक्तिगत विशेष कार्य के लिए 10 (दस) लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

#### 20 स्टाफ सलाहकार की नियुक्ति

- 20.1 आयोग, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है, या नियमित पदों को दाखिल करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों, काम में तेजी लाने के लिए, आयोग को अपने कार्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन में सहायता करने और सचिव को आगे कदम उठाने का निर्देश देने के लिए एक कर्मचारी सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।
- 20.2 आयोग ने एक स्टाफ सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करके, और जहाँ तक संभव हो, इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए चार सप्ताह की अवधि देकर, कार्यकाल के आधार पर आवेदन आमंत्रित करेगा।
- 20.3 नोटिस प्रकाशित करने से पहले, आयोग के सचिव एक नियमित पद के लिए भर्ती को नियंत्रित करने वाले आयोग के विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए योग्यता और अनुभव की आवश्यकताओं की पहचान करेंगे।
- 20.4 स्टाफ सलाहकार को योग्यता और 3 से 15 या अधिक वर्षों के अनुभव की अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और एक समेकित शुल्क की पेशकश की जा सकती है जो मूल वेतन और उस पद के महंगाई भत्ते के बराबर होगी जिसके लिए स्टाफ सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है।
- 20.5 स्टाफ सलाहकार को कार्यकाल के आधार पर शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जहां देय शुल्क वर्ष के लिए 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

- 20.6 आयोग एक चयन समिति का गठन करेगा जो उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेगी और आयोग के अनुमोदन के लिए स्टाफ सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी।
- 20.7 न्यूनतम योग्यता और आयु मानदंड: इच्छुक उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की तिथि पर 60 वर्ष की आयु तक का उम्मीदवार एक व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में काम करने के लिए पात्र है और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक आयोग को सेवाएं प्रदान कर सकता है; बाद में कोई आयु छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 21 एकल स्रोत चयन**  
आयोग द्वारा उपयुक्त मामलों में एकल स्रोत चयन का सहारा लिया जा सकता है जहां यह एक स्पष्ट लाभ को दर्शाता है, क्योंकि कार्य परामर्शदाता द्वारा किए गए पिछले कार्य की स्वाभाविक निरंतरता को दर्शाता है, या जहां एक तत्काल चयन आवश्यक है, या छोटे कार्यों के लिए जहां देय शुल्क 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है या जहां केवल एक फर्म के पास योग्यता या कार्य का अनुभव है।
- 22 हित द्वंद्व**  
परामर्शदाता को ऐसे किसी भी कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जो अन्य ग्राहकों के प्रति उसके पूर्व या वर्तमान दायित्वों के विरोध में हो या जो उसे उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम न होने की स्थिति में रखता हो।
- 23 सलाहकारों की नियुक्ति**  
नियुक्ति के लिए चयनित सलाहकार को इन विनियमों के अंत में अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, ऐसे बदलावों और संशोधनों को अलग-अलग मामलों में उपयुक्त माना जाएगा।
- 24 आयोग की निहित शक्ति की बचत**  
इन प्रावधानों में कुछ भी आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग मामले की विशेष परिस्थितियों या मामलों के वर्ग को देखते हुए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया से हटना आवश्यक या समीचीन समझता है।
- 25 संशोधन करने की सामान्य शक्ति**  
आयोग उचित समझे जाने पर किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर, उन उद्देश्यों को पूरा करने के हेतु से इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है जिसके लिए ये विनियम बनाए गए हैं।
- 26 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**  
यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कुछ भी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

आयोग के आदेश द्वारा,

वी. के. धर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./49/2023-24]

### अनुसूची

एक (प्रथम) भाग (परामर्शदाता) के \_\_\_\_\_ और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे (द्वितीय) भाग के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इसके बाद "आयोग" रूप में जाना जाएगा) के बीच \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिवस को किए गए समझौते।

जबकि आयोग ने परामर्शदाता के रूप में पहले भाग की पार्टी को शामिल किया है और पहले भाग की पार्टी आयोग को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसमें निहित नियमों और शर्तों पर सहमत हुई है।

अब, यह प्रस्तुत करता है कि गवाह और पक्षकार क्रमशः निम्नानुसार सहमत हैं:

- 1) पहले भाग (परामर्शदाता) का पक्ष आयोग के और उन अधिकारियों और प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति स्वयं को प्रस्तुत करेगा जिनके अधीन उसे समय-समय पर आयोग द्वारा रखा जा सकता है।

- 2) पहले भाग (परामर्शदाता) की पार्टी अनुसूची - 'ए' में निहित असाइनमेंट को \_\_\_\_\_ से शुरू होने वाली अवधि के भीतर पूरा करेगी।
- 3) पहले भाग (परामर्शदाता) की पार्टी को निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा:
- 4) भुगतान की अनुसूची निम्नानुसार होगी:
- 5) परामर्श कार्य के संबंध में स्थानीय यात्राओं के लिए पहले भाग की पार्टी को कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। (शायद किसी व्यक्तिगत असाइनमेंट के लिए सहमत शर्तों के आधार पर भिन्न)
- 6) शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा उस समय लागू कानून के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा।
- 7) गोपनीय प्रकृति की कोई भी जानकारी, जो इस अनुबंध की विषय वस्तु के आधार पर परामर्शदाता या उसके किसी कर्मचारी के ज्ञान या कब्जे में आती है, सलाहकार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को किसी भी तरीके से प्रकट नहीं की जाएगी। कानून के अनुसार शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस खंड का कोई भी उल्लंघन, सलाहकार को आयोग को भुगतान करने के दायित्व के अधीन होना चाहिए, ऐसा मुआवजा, जैसा कि आयोग द्वारा प्रकट की गई जानकारी की प्रकृति, तरीके और मकसद को ध्यान में रखते हुए और इस तरह के अनधिकृत प्रकटीकरण से हुई क्षति की सीमा को ध्यान में रखते हुए तय किया जा सकता है।
- 8) पहले भाग की पार्टी यह वचन देती है कि, यह असाइनमेंट अन्य ग्राहकों के लिए इसके पूर्व या वर्तमान दायित्व के विरोध में नहीं होगा न ही यह खुद को उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में रखेगा।
- 9) यदि पहले भाग के पक्ष की ओर से पार्टियों के बीच सहमत समय-सारिणी के भीतर काम पूरा करने में कोई चूक होती है, तो दूसरे भाग (आयोग) की पार्टी पहले भाग (सलाहकार) की पार्टी के जोखिम और लागत पर किसी अन्य एजेंसी से काम पूरा करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- 10) आयोग बिना कोई कारण बताए सलाहकार की नियुक्ति को रोकने, समाप्त करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे मामलों में पहले भाग की पार्टी (परामर्शदाता) को इस तरह के फौजदारी, समाप्ति, या कार्य को रद्द करने से पहले पूरा किए गए काम के हिस्से को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है और आयोग का निर्णय निर्णायक और बाध्यकारी हो। ऐसे मामलों में निर्धारित और भुगतान किया गया पारिश्रमिक अंतिम भुगतान माना जाएगा।
- 11) इस समझौते से पार्टियों के बीच उत्पन्न किसी भी मतभेद या विवाद के मामले में, उसे आयोग द्वारा नामित व्यक्ति की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन होगी।
- 12) सलाहकार के कार्मिक  
पहले भाग की पार्टी (सलाहकार) नाम, पद और योग्यता के साथ कर्मियों का विवरण प्रदान करेगी।
- 13) कर्मियों का निष्कासन और / या प्रतिस्थापन  
जब तक आयोग अन्यथा सहमत न हो, प्रमुख कर्मियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि, किसी कारण से, परामर्शदाता के उचित नियंत्रण से परे, यह आवश्यक हो जाता है कि कोई प्रमुख कार्मिक हो, तो परामर्शदाता उसके स्थान पर समकक्ष या बेहतर योग्यता वाला व्यक्ति प्रदान करेगा, जो आयोग को स्वीकार्य होगा।
- 14) यदि आयोग को पता चलता है कि (1) कर्मियों में से किसी ने गंभीर कदाचार किया है या उस पर आपराधिक कार्य करने का आरोप लगाया गया है या (2) किसी भी कार्मिक के प्रदर्शन से असंतुष्ट होने का उचित कारण है, तो सलाहकार सचिव के लिखित अनुरोध पर, इस आधार को निर्दिष्ट करते हुए स्वीकार्य योग्यता और अनुभव के साथ एक व्यक्ति को तुरंत प्रतिस्थापन के रूप में आयोग को प्रदान करेगा। सलाहकार के पास किसी भी हटाने योग्य और/या कर्मियों के प्रतिस्थापन से उत्पन्न या आकस्मिक होने वाली अतिरिक्त लागत के लिए कोई दावा नहीं होगा।



15) पहले भाग के दल के नोडल व्यक्ति (सलाहकार) श्री \_\_\_\_\_

16) आयोग की ओर से सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, नोडल अधिकारी होंगे।

17) कोई अन्य नियम और शर्तें।

18) नियुक्ति के विषय पर भारत सरकार के सामान्य निर्देशों में निहित प्रावधान लागू होंगे।

इसके साक्ष्य में आयोग की ओर से आयोग के पहले भाग (परामर्शदाता) और \_\_\_\_\_ की पार्टी ने पहले लिखे गए दिन और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

\_\_\_\_\_ की उपस्थिति में \_\_\_\_\_ द्वारा पहले भाग की पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित \_\_\_\_\_ द्वारा आयोग के लिए और \_\_\_\_\_ की उपस्थिति में आयोग की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
(FOR UT OF JAMMU & KASHMIR AND UT OF LADAKH)  
NOTIFICATION**

Jammu, the 6th April 2023

**No. JERC-JKL/Reg/2023/09:** In exercise of powers conferred on it by subsection (4) of Section 91 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:

**1. Short Title and Commencement**

- 1.1 These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Appointment of Consultants) Regulations, 2023.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette:

**2. Definitions**

- 2.1 In these regulations unless the context otherwise requires: -
- a. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
  - b. "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh ;
  - c. "Committee" means the committee constituted by the Commission for evaluation of request of proposals;
  - d. "Consultant" includes any individual - not in the employment of the Commission, firm, body or association of persons, who or which possesses or has access to any specialized knowledge, experience or skill;
  - e. "Secretary" means the Secretary of the Commission.
- 2.2 Words or expressions occurring in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.

**3. Scope of Work**

- 3.1 The Commission may from time to time appoint Consultants for executing specialized tasks for which skills are either not available within the staff of the Commission or where the nature of job is specific and time-bound or where the Commission considers appointment of consultant to be conducive or more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, cost, time or for any other consideration or performing such other functions and for generally assisting the Commission in the performance of its functions, if the Commission considers it necessary.
- 3.2 The terms and conditions of engagement of Consultants will be drawn up in each case and agreed to between the Consultant and the Commission prior to the award of work.

- 3.3 The terms of engagement would specify the exact nature of the tasks to be undertaken by the Consultant, the time allowed for the completion of each task, and the specific outputs that are to be provided by the Consultant in relation to each work as per terms of reference approved in this regard.

#### 4. Period of Appointment

- 4.1 The consultant shall be appointed for the minimum period:

Provided that the period of the initial appointment of a consultant on any specific assignment shall not normally exceed two years:

Provided further that period of appointment may be extended subject to the condition that the maximum period of continuous appointment of a consultant in no case shall exceed four years.

#### 5. Categorisation of Consultants

- 5.1 The consultants shall be categorized as: (a) Institutional consultants, (b) Individual consultants, (c) Professional, Expert, and (d) Staff Consultant.

#### 6. Institutional Consultant

The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, maybe more appropriately provided by a firm, or a company or an association or body of persons, shall engage an Institutional Consultant.

#### 7. Individual Consultant

- 7.1 The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, can be more efficiently performed by an individual having required qualifications and experience for an assignment, for which teams of personnel are not required, may decide to engage an Individual Consultant.

- 7.2 Individual Consultant may also be appointed for assisting the Commission in the discharge of its function-, if the Commission is satisfied that there has been an increase in the quantum of work of the Commission or a regular post could not be filled due to various constraints.

- 7.3 The Headquarters of the individual consultant normally shall be the Headquarters of the Commission.

#### 7.3 Categorization of Individual Consultants

- 7.3.1 Based on experience, individual consultants shall be categorized as

Category	Minimum Experience in the Area of Appointment
Advisors	15 years
Senior Consultants	10 years
Consultants	3years

- 7.3.2 The Commission may prescribe minimum educational qualifications, depending on the nature of the work, and the relevant professional qualifications related to subject area of the consultancy.

- 7.3.3 The Commission may in appropriate case, for reasons to be recorded in writing, relax the educational qualifications, keeping in view the overall expertise of the person being considered for engagement as individual consultant.

#### 8. Professional Expert

The Commission on being satisfied on the need for the professional expertise of specialized nature may decide to engage a professional expert for advice on the issue of urgent and specialized nature.

#### 9 Staff Consultant

Staff Consultant may be appointed for assisting the commission in discharging its functions. If the Commission is satisfied that there has been increasing in the quantum of work of the Commission or a regular post could not be filled due to various constraints.

**10 Appointment of Institutional Consultant**

- 10.1 The Commission, on being satisfied that there is a need to avail services of the Institutional Consultant for any task, shall direct the Secretary to prepare or cause to be prepared the detailed terms of reference.
- 10.2 The Secretary shall prepare or cause to be prepared the detailed terms of reference for the appointment of Consultant for any specific task and shall obtain approval of the Commission.
- 10.3 The terms of reference shall be prepared to specify the objectives, goals, and scope of the assignment and provide background information including a list of existing relevant studies and basic data to facilitate the consultant in the preparation of his proposal:
- Provided that the terms of reference shall also list the services and surveys necessary to carry out the assignment and the expected outputs (for example reports, data, surveys, etc.) linked to each task included in the terms of reference.
- Provided further that where transfer of knowledge-, and training is an objective, the terms of reference shall detail the number of staff to be trained.
- 10.4 After approval of the terms of reference by the Commission, the Secretary shall issue or cause to be issued the request for proposals to invite proposals for appointment as Institutional Consultant and give such publicity as may be considered appropriate by the Commission.
- 10.5 The Commission may decide either to invite combined technical and financial proposals or separate technical and financial proposals.
- 10.6 The Commission may prescribe the minimum qualifying marks for the technical bid.

**11 Request for proposals**

The request for proposals shall include the following: -

- 11.1 A letter of invitation stating the intention of the Commission to enter into a contract for the provision of consultancy services, the details of the plan, and the date, time, and address for submission of proposals.
- 11.2 Information to the consultants shall contain all necessary information that will help them to prepare responsive proposals by providing information on the evaluation process and by indicating the evaluation criteria and factors and their respective weights and the minimum pre-qualification score and special qualifying clause if any.
- 11.3 Terms of reference as prepared in this regard as per regulation (10.3) above.

**12 Receipt of proposals**

- 12.1 The Commission shall prescribe the time within which the Consultants shall submit their proposals.
- 12.2 The Commission may, where it considers appropriate, decide to extend the time limit for the submission of proposals.
- 12.3 No amendment to the technical or financial proposals shall be accepted after the expiry of the time limit.
- 12.4 The proposals shall be submitted in sealed cover(s).

**13 Evaluation of proposals**

- 13.1 The proposal shall be evaluated both on the basis of technical competence as well as quoted cost.
- 13.2 Where the Commission decides that the technical and financial proposals be evaluated separately, the Committee shall not have access to the financial proposals, until the evaluation of the technical proposals is completed.
- 13.3 The proposal shall be evaluated by a Committee appointed by the Commission in this regard. The Committee may enter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations are conducted, the same will be conducted prior to the pre-qualification of consultants. Financial negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for staff months, contingency amounts, lump sum reimbursement of travel and living expenses, and payment terms.

**14 Technical Evaluation**

- 14.1 Technical evaluation will be done by the Committee appointed under regulation (13.3) above taking into account the criteria given under regulation (14.2) below.
- 14.2 Each technical criterion shall be marked on a scale of 1 to 100 and then the marks for each criterion shall be weighted to become average technical scores. Weights in the following ranges will be used by the Committee, with the approval of the Commission, to calculate the weighted average technical score for each proposal: -

Criterion	Range of Weights
Consultant's relevant experience for the assignment	0.10 to 0.40
Quality of the methodology proposed	0.20 to 0.50
Qualifications of the key staff proposed	0.30 to 0.60
Extent of transfer of knowledge to the staff of the Commission	0.05 to 0.35

**Note :** The mix of weights approved by the Commission will total to 1.

The Evaluation Committee appointed under Regulation (13.3), shall decide the weightage to be

allocated (in the range prescribed above) to each of the parameters for the purpose of technical evaluation of bids, and obtain the approval of the Chairperson of the Commission for the allocation. The Commission shall have the right of distribution of marks on the basis of the nature and requirement of the assignment.

- 14.3 Where the assignment depends critically on the performance of the key staff, the proposal shall be evaluated on the qualifications of the individuals proposed to be appointed using the following criteria: -
- General qualifications: General education and training, length of experience, positions held, time with the consulting firm as staff, experience in developing countries, etc.
  - Adequacy for the assignment: Education, training, experience in the specific sector, field, subject, and relevance to the particular assignment.

- 14.4 After the technical evaluation is completed, the Commission shall inform those Consultants whose proposals did not meet the minimum qualifying marks or were considered non-responsive to the terms of reference, and their financial proposals will be returned unopened after completing the selection process.
- 14.5 Simultaneously, those Consultants who have secured the minimum qualifying marks after technical evaluation shall be informed about the date and time for opening the financial proposals, giving sufficient time for the Consultants to be present at the opening should they so desire.

## 15 Financial Evaluation

- 15.1 The financial proposals of the technically qualified Consultants will be opened by the Committee in the presence of consultants or their representatives whose bids are shortlisted for financial evaluation. The proposed prices shall be read aloud and recorded in minutes of the proceedings.
- 15.2 The Secretary will cause a review of the financial proposals to be done. Arithmetical errors will be corrected. The cost shall be quoted in Indian Rupees.
- 15.3 The proposal with the lowest cost will be given a financial score of 100 and other proposals will be given financial scores that are inversely proportional to their cost.

## 16 Evaluation of financial and technical scores

- 16.1 The total score shall be obtained by weighting the technical and financial scores and adding them and the consultant with the highest total score shall be invited by the Commission to enter into a contract within the prescribed time limit. The weight for the technical and financial score shall be as prescribed by the Commission in each case taking into account the complexity of the assignment and the relative importance of quality. However, the weight will never exceed 0.3 for the financial score in any case.
- 16.2 The Commission may reject any or all proposals if they are found to be unresponsive or unsuitable either because they represent major deficiencies in complying with the terms of reference or they involve cost substantively higher than the original estimate.

## 17 Appointment of Individual Consultants

Individual consultants may be selected on the basis of their qualifications and experience for the assignment. The Commission may direct the Secretary to prepare the terms of reference indicating the scope of work and other terms and conditions as per the requirement, which shall be submitted to the Commission for approval. Individual Consultants may be selected on the basis of references or from amongst those who have applied

against the notice published by the Commission in this regard, as the case may be. Their suitability shall be judged on the basis of academic background, experience, and adequate knowledge of local conditions, administrative system, and government organization.

- 17.1 **Minimum Qualification and Age criteria:** The aspirant candidate should possess (a) a Bachelor's degree in Engineering from a recognized college/ university. (b) The candidate must have a clear understanding of the Electricity Act, 2003, the rules and regulations made under the Act, and the applicable policies, legal and regulatory framework related to the power sector. (c) Proven experience in providing assistance to States/Joint/Central Electricity Regulatory Commissions during the regulatory proceedings involved during the tariff determination process and related matters. (d) the candidate up to the age of 60 years on the date of application are eligible to work as an individual consultant and can render services to the Commission till attaining the age of 65 years; afterward no age relaxation shall be allowed.

## 18 Fees and Other Charges in Case of Individual Consultants

- 18.1 Except where the Commission directs otherwise, the individual consultant shall be appointed generally on a consolidated fee basis, depending on the nature of the assignment or monthly fee basis.
- 18.2 No payments in addition to the consolidated fee in accordance with sub-regulation (1) shall be made in the case of individual consultants:

Provided that the Commission may allow an additional amount not exceeding 10% of the fee payable to the consultant to cover expenditures of contingent nature.

- 18.3 Where the consultant has to incur expenditure on travel to and stay at a place away from the headquarters of the Commission, the Commission shall reimburse the cost of travel by an appropriate class, not lower than that permitted to a Group A Officer of the Central Government and authorize payment of Daily Allowance, in addition to the fee and other charges payable under these regulations, for such number of days as the Commission may consider appropriate.
- 18.4 The fee and other charges payable to individual consultants under these regulations shall also be payable to former and retired Government servants appointed as consultants by the Commission.
- 18.5 Fee for Individual Consultants

Category	Maximum Fee per man day	Daily Allowance
Advisors	Rs.7500/-	Actual for boarding and lodging expenses
Senior Consultants	Rs.5500/-	Actual for boarding and lodging expenses
Consultants	Rs.3000/-	Actual for boarding and lodging expenses

### Note:

1. The Commission reserves the right to decide about the fee payable to the Individual Consultant on a daily/monthly basis based on the experience and credentials of the Individual consultant as deemed proper by the Commission.
2. The Commission also reserves the right to specify the amounts permissible as daily Allowance, determine the reasonable limits within which actual expenses are to be allowed, on a case-to-case basis, and assess the reasonableness of any claim submitted thereof.

- 19 **Appointment of Professional Experts** On the Commission having decided to engage professional experts, the Secretary of the Commission shall formalize the proposals. He/ She shall prepare a list of not less than two professionals having the requisite expertise in the specialized field, their willingness to accept consultancy work, and the fee demanded by each of them.

The Commission may approve the name of the expert for engagement as a consultant on payment of such fee and on such terms, as may be considered appropriate provided that the fee so decided shall not exceed Rs. 10 (Ten) lakhs for an individual specialized assignment of work.

**20 Appointment of Staff Consultant**

- 20.1 The Commission, on being satisfied that there has been an increase in the quantum of work of the commission, or difficulties arising in filing regular posts, may decide to engage a staff consultant to expedite the work, to assist the commission in the discharge of its functions effectively and direct the Secretary to take further steps.
- 20.2 The Commission, after having decided to engage a staff Consultant, shall invite applications on a tenure basis, by publishing a notice in the National Dailies and on the Commission's Website, and by giving, as far as possible, a period of four weeks for inviting application by the interested persons.
- 20.3 Before publishing the notice, the Secretary of the Commission shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission's Regulations governing recruitment against a regular post.
- 20.4 The staff consultant may be categorized based on qualification and length of experience ranging from 3 to 15 or more years and offered a consolidated fee which shall be equivalent to basic pay plus dearness allowance of the post against which the staff consultant is being engaged.
- 20.5 The staff consultant shall be engaged on a tenure basis, initially for a period of one year where the fee payable does not exceed Rs.10 lakhs for the year.
- 20.6 The Commission shall constitute a Selection Committee which shall interact with the candidates and recommend names of suitable persons for engagement as staff consultants for approval of the Commission.
- 20.7 Minimum qualification and age criteria: The aspirant candidate should possess Bachelor's degree in Engineering from a recognized college/ university. The candidate up to the age of 60 years on the date of application is eligible to work as an individual consultant and can render services to the Commission till attaining the age of 65 years; afterward no age relaxation shall be allowed.

**21 Single source selection**

Single source selection may be resorted to by the Commission in appropriate cases where it represents a clear advantage because the tasks represent a natural continuation of previous work carried out by the consultant, or where an immediate selection is essential, or for small assignments where the fee payable does not exceed Rs.10 lakhs or where only one firm is qualified or has experience for the assignment.

**22 Conflict of interest**

Consultant shall not be hired for any assignment that would be in conflict with his prior or current obligations to other clients or that may place him in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

**23 Appointment of Consultants**

The consultant selected for appointment shall be required to execute an agreement in the format given in the Schedule at the end of these regulations, with such variations and modifications considered appropriate in individual cases.

**24 Saving of the inherent power of the Commission**

Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure prescribed in these Regulations.

**25 General power to amend**

The Commission may at any time and on such terms, as it may think fit, amend any provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives for which these Regulations have been framed.

**26 Power to remove difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

By Order of the Commission,

V. K. DHAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./49/2023-24]

**SCHEDULE**

Articles of Agreement made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ one (first) part (Consultant) and the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (herein after called "the Commission") of the other (Second) part.

Whereas the Commission has engaged the party of the first part as a Consultant and the party of the first part has agreed, to provide the consultancy services to the Commission, on the terms and conditions herein after contained.

Now, these presents witnesses and the parties hereto respectively agree as follows:

- 1) The party of the first part (Consultant) shall submit himself to the orders of the Commission and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Commission.
- 2) The party of the first part (Consultant) shall complete the assignment as contained in Schedule – 'A' within a period of \_\_\_\_\_ commencing from \_\_\_\_\_.
- 3) The party of the first part (Consultant) shall be paid as under:
- 4) The schedule of payments shall be as under:
- 5) No TA/DA shall be admissible to the party of the first part for local journeys in connection with the consultancy assignment. (*maybe varied depending on terms agreed for any individual assignment*)
- 6) The payment of the fee shall be made by the Commission after the deduction of tax at source in accordance with the law for the time being in force.
- 7) Any information of confidential nature, which comes to the knowledge or into the possession of the consultant or any of its employees by virtue of the engagement subject matter of this contract shall not be disclosed by the consultant or its employees to any unauthorized person in any manner. Any breach of this clause without prejudice to any other action that may be initiated according to law-, shall also subject the consultant to a liability to pay to the Commission such compensation as may be decided by the Commission keeping in view the nature, manner, and motive of the information disclosed and the extent of the damage caused by such unauthorized disclosure.
- 8) The party of the first part undertakes that this assignment shall not be in conflict with its prior or current obligation to other clients nor shall it place itself in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.
- 9) In case of any default on the part of the party of the first part in the completion of the work within the time schedule agreed to between the parties as herein above, the party of the second part (the Commission) shall be at liberty to get the work completed from any other agency at the risk and cost of the party of the first part (Consultant).
- 10) The Commission reserves its right to foreclose, terminate or cancel the engagement of the consultant without assigning any reasons. In such cases party of the first part (Consultant) shall be paid remuneration after taking into consideration the portion of work completed prior to such foreclosure, termination, or cancellation of the engagement as may be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be conclusive and binding. The remuneration so fixed and paid shall be deemed to be the final payment in such cases.
- 11) In case of any differences or disputes between the parties arising out of this AGREEMENT, the same shall be referred for arbitration of a person nominated by the Commission. The proceedings shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act 1996, as amended from time to time.
- 12) Consultant's Personnel  
The party of the first part (Consultant) shall provide a Description of personnel with names, positions and qualifications.
- 13) Removal and/or replacement of the personnel  
Except as the Commission may otherwise agree, no change shall be made in the key personnel. If, for any reason, beyond the reasonable control of the Consultant, it becomes necessary any of the key personnel, the Consultant shall forthwith provide as a replacement a person of equivalent or better qualifications, which is acceptable to the Commission.
- 14) If the Commission finds that any of the personnel (1) committed serious misconduct or has been charged with having committed a criminal action or (2) have reasonable cause to be dissatisfied with the performance of any of the personnel, then the Consultant shall, at the Secretary's written request, specifying the ground therefore, forthwith provides as a replacement a person with qualification and experience acceptable to the Commission. The Consultant shall have no claim for additional costs arising out of or incidental to any removable and /or replacement of personnel.

15) Nodal Person of the party of the first part (Consultant) Mr. \_\_\_\_\_

16) The Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, shall be the Nodal Officer on behalf of the Commission.

17) Any other terms and conditions.

18) In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement, the provisions contained in the general instructions of the Government of India on the subject of engagement of consultants shall apply.

IN WITNESS WHERE OF the party of the first part (Consultant) and \_\_\_\_\_ to the Commission on behalf of the Commission have hereto put their hands on the day and the year first above written.

Signed by \_\_\_\_\_ the party of the first part in the presence of \_\_\_\_\_ Signed by \_\_\_\_\_ to the Commission for and on behalf of the Commission in the presence of \_\_\_\_\_